वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कार्यों की समीक्षा

■ जिला कलेक्टरों को अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने के निर्देश

रायपुर. नवभारत समाचार. अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सरजियस मिंज द्वारा मंत्रालय स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से चर्चा कर राज्य के दस जिलों दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव, कवीरधाम, सरगुजा, कोरिया, जशपुर के लिए मंजूर एकीकृत कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की. प्रदेश के दस जिलों के लिए 250 करोड़ रुपए की यह कार्य योजना स्वीकृत की जा चुकी है. श्री मिंज ने जिला कलेक्टरों से कहा कि एकीकृत कार्य योजना के तहत प्रत्येक जिले को आबंटित 25 करोड़ रुपए की निधि से अधिक से अधिक कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाए, जिससे स्वीकृत कार्य पूर्ण हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए. श्री मिंज ने कहा कि योजना के तहत ऐसे कार्य लिए जाएं, जिससे ग्रामीणजनों को सीधे लाभ पहुंचता हो. जिले की उन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किए जाएं जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में हैं. उन्होंने माह मार्च 2011 तक प्राप्त आबंटन को व्यय किए जाने संबंधी कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए. वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संचालक पंचायत और समाज सेवा आलोक अवस्थी भी उपस्थित थे.

श्री मिंज ने जिला कलेक्टरों से कहा कि जिन जिलों में कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां इसी माह की 14 तारीख तक कार्य स्वीकृत करें. सभी स्वीकृत कार्य तुरन्त ही शुरू किए जाएं. उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऐसे कार्य लिए जाएं जिससे ग्रामीणजनों को सीधे लाभ पहुचंता हो. जिले की उन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किए जाएं जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में हैं. जिला कलेक्टरों द्वारा कार्य स्वीकृति के लिए पूछे गए प्रश्न के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि तात्कालिक महत्व के कार्यों की स्वीकृति के लिए योजना के तहत गठित समिति ही सक्षम है. उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि इस योजना में ऐसे कार्य लें जो जनता को सीधे लाभांवित कर सकें. योजना की मार्गदर्शिका अनुसार सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से कराए जाने वाले कार्यों को लिया जा सकता है. श्री मिंज ने कहा कि ऐसे कार्य स्वीकृत किए जाएं, जिनमें विभागीय आबंटन की उपलब्धता नहीं है और जो विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़ सकें. उन्होंने कहा कि गांवों को जोड़ने वाले मार्ग छोटे पुल-पुलियों का निर्माण प्राथमिकता से कराएं. श्री मिंज ने कहा कि योजना की प्रगति की जानकारी के लिए जिलों को प्रपत्र भेजे गए हैं. प्रपत्र में सेक्टरवार प्रगति की 17 जनवरी को होने वाली वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रगति से केन्द्र को अवगत कराया जा सके. सभी जिला कलेक्टरों को 17 जनवरी को आयोजित होने वाली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए अपने एन.आई.सी. केन्द्र में जिले की योजना की जानकारी सहित निर्धारित समय पर उपस्थित रहने को भी कहा गया.